



आयुक्त का कार्यालय), अपीलस()
Office of the Commissioner,
केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद आयुक्तालय
Central GST, Appeal Commissionerate- Ahmedabad
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.
CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015
☎ : 079-26305065 टेलीफैक्स : 079 -26305136



रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(GST)12/EA-2/Ahd-South/2018-19 / 10768 to 10772

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-JC-01-2019-20
दिनांक Date : 17-05-2019 जारी करने की तारीख Date of Issue _____

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

29/05/2019

Passed by Shri. Sachin Gusia, Joint.Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. CGST/WS07/Ref-151/PV/AC/18-19 दिनांक: 19.07.2018
issued by Assistant Commissioner, Div-VII, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
Brooklyn Transformers and electricals
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal issued under the Central Excise Act 1944, may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 2 ...



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैनटल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद-380016

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

6(I) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty where penalty alone is in dispute."

II. Any person aggrieved by an Order-In-Appeal issued under the Central Goods and Services Tax Act,2017/Integrated Goods and Services Tax Act,2017/ Goods and Services Tax(Compensation to states) Act,2017,may file an appeal before the appropriate authority.



ORDER IN APPEAL

The below mentioned departmental appeal have been filed by Assistant Commissioner, Central GST, Division VII, Ahmedabad South Commissionerate, [for short – ‘adjudicating authority’] under Section 107 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the details of which are as follows:

Sr. No.	Name of the respondent	OIO No. & date issued under Form GST RFD 06	Review Order No. passed by the Commissioner, CGST, Ahmedabad South Comm'rate [in terms of Section 107(2) of the CGST Act, 2017]	Appeal No.
1	M/s. Brooklyn Transformers & Electricals (GSTN NO. 24AAWPP5238R1ZN)	CGST/WS07/Ref-151/PV/AC/2018-19 dated 19.07.2018	07/2018-19 dtd 24.01.2019	012/EA-2/AHD-I/2018-19

2. Briefly, the facts of the case are that the respondent filed manually refund claim, vide Circular No. 17/17/2017-GST dated 15-11-2017, for the months of March-2018 in terms of Section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on account of supplies to SEZ unit/ SEZ Developer with payment of tax i.e. IGST amounting of Rs. 5058/-. The adjudicating authority vide his impugned OIO, mentioned in the table *supra*, sanctioned the refund claim.

3. On the refund claims being sent for post audit, it was observed by the Assistant Commissioner(Audit), CGST, Ahmedabad South that the respondent has not submitted the endorsed copies of invoice for supply of goods or services in SEZ. Further, The Assistant Commissioner, Central GST, Div-VII, Ahmedabad-South has informed to the appellants that the full amount of refund claim of Rs. 5058/- has been recovered alongwith interest of Rs 372/- from the respondent and the same has been shown in statement DRC-03 vide entry No. DC2401190393971 dated 22.01.2019 against impugned order. Thereafter on the impugned orders-in-original, having been examined and it is found that the said refund sanctioned is not proper and legal as claimant has not submitted the endorsed copies of invoice for supply of goods or service in SEZ. The Commissioner, CGST South Commissionerate vide his aforementioned Review Orders, directed the Assistant Commissioner, Central GST, Div-VII, Ahmedabad South to file the aforementioned appeal raising the following grounds:

- that the respondent has not submitted the endorsed copies of invoice for supply of goods or service in SEZ whereas the adjudicating authority at para 6 of impugned order found that the invoices for supply of Duty free goods are endorsed by the SEZ, as per SEZ norms;
- that the adjudicating authority has erred by sanctioning the refund of Rs. 5058/- which needs to be recover and appropriate the amount erroneously refunded to the respondent with interest.



Jainis
11-1-19

4. Personal hearing in respect of the appeal was fixed on 28.03.2019 & 25.04.2019. The respondent, vide his letter received on 01.05.2019, informed that they have paid a challan of Rs. 5430/- against the impugned order and they are not interested in giving any further hearing. The respondent also attached a copy of payment receipt and requested to consider the same.

5. I have gone through the facts of the case, the impugned original orders, the grounds raised in the review orders mentioned *supra* and the letter received from the respondent. I find that the only question to be decided is whether the refund granted to the respondent vide the impugned OIOs, are erroneous or otherwise.

6. The matter deals with refund on account of supplies to SEZ unit/ SEZ Developer with payment of tax and therefore before moving forward, let me first reproduce the relevant rules which enables a person to seek refund of tax in such a situation, viz.

RULE 89. Application for refund of tax, interest, penalty, fees or any other amount. —

(1) Any person, except the persons covered under notification issued under section 55, claiming refund of any tax, interest, penalty, fees or any other amount paid by him, other than refund of integrated tax paid on goods exported out of India, may file an application electronically in FORM GST RFD-01 through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner :*

Provided that any claim for refund relating to balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 may be made through the return furnished for the relevant tax period in FORM GSTR-3 or FORM GSTR-4* or FORM GSTR-7 as the case may be :*

Provided further that in respect of supplies to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer, the application for refund shall be filed by the -

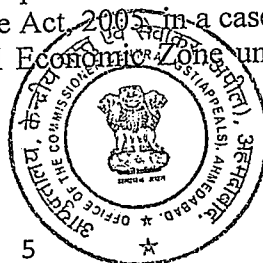
(a) supplier of goods after such goods have been admitted in full in the Special Economic Zone for authorised operations, as endorsed by the specified officer of the Zone;

(b) supplier of services along with such evidence regarding receipt of services for authorised operations as endorsed by the specified officer of the Zone :

Rule 2(d) and 2(e) of Rule 89 of CGST Rules 2017:

(d) a statement containing the number and date of invoices as provided in rule 46 along with the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) in the case of the supply of goods made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;

(e) a statement containing the number and date of invoices, the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) and the details of payment, along with the proof thereof, made by the recipient to the supplier for authorised operations as defined under the Special Economic Zone Act, 2005, in a case where the refund is on account of supply of services made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;



Jain
12/05/19

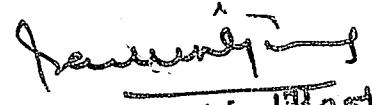
7. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the Appeal and the Written Submission filed by the respondent. The primary ground raised by the department is that the respondent has not submitted the endorsed copies of invoice for supply of goods or service in SEZ. Prima facie, I find that the respondent, vide his letter received on 01.05.2019, informed that they have paid a challan of Rs. 5430/- against the impugned order and they are not interested in giving any further hearing. Thus, I find that the ground raised in the departmental appeal, that the adjudicating authority has erred by sanctioning the refund of Rs. 5058/- is tenable.

8. In view of the foregoing, I find that there is merit in the departmental appeal and therefore, I set aside the impugned OIOs to the extent they have erroneously sanctioned the refund of Rs. 5058/-.

9. The departmental appeals are allowed and the impugned order is set aside to the extent it has erroneously sanctioned the refund as mentioned in above para. The prayer of the department for recover and appropriate the amount erroneously refunded to the respondent with interest is also allowed.

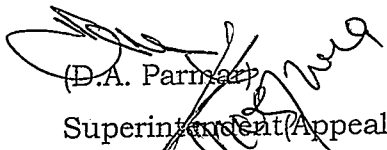
10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the department-appellant stands disposed of in above terms.


(सचिन गुंसिया)
संयुक्त आयुक्त (अपील)

Date : .05.2019

Attested


(D.A. Parmar)
Superintendent (Appeals),
Central Tax, Ahmedabad

By RPAD.

To,

M/s. Brooklyn Transformers & Electricals,
Jayantilal Premjibhai Patel,
5, Kameshwar Kunj, Opp. Nehru Nagar,
Polytechnic, S.M.Road, Ahmedabad-380015

Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad Zone .
2. The Commissioner, Central Tax, Ahmedabad South Commissionerate.
3. The Assistant Commissioner, CGST, Division-VII, Ahmedabad South Commissionerate.
4. The Assistant Commissioner, System, Central Tax, Ahmedabad South Commissionerate.
5. Guard File.
6. P.A.

